सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹02

सांध्यकालीन समाचार पत्र

स्वराज इंडिया

कानपुर, बुधवार, 02 जुलाई, 2025
वर्षः 02, अंकः 179, पृष्ठः 8+4

अमेरिका ने रोक दी यूक्रेन की सैन्य मदद

» Pg 12

इनसाइड डील शब्द ने माननीय को क्यों कराया बैड फील... » Pg 07

अपना दल एस में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बगावत!

अपना मोर्चा नामक संगठन ने खोला अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा

» अनूप अवस्थी, स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा धमाका करते हुए 'अपना मोर्चा' नाम से एक नए राजनीतिक मोर्चे की घोषणा की गई है। राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में मोर्चा के संयोजक चौधरी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पटेल ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष सिंह पटेल ने पार्टी को "पति-पत्नी प्राइवेट लिमिटेड" बना दिया है और कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष और समर्पण को दरकिनार कर दिया है।

चौधरी ब्रजेंद्र ने कहा कि कार्यकर्ता ही 'अपना दल (सोनेलाल)' के असली स्तंभ थे, लेकिन पिछले दस वर्षों में पार्टी को निजी स्वार्थ, पदलोलुपता और साजिशों का अड्डा बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुप्रिया पटेल ने अपने पति को अध्यक्ष बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को धोखे में रखा, विधायकों को किनारे किया और कुर्मी समाज को हाशिए पर धकेल दिया।

उन्होंने दावा किया कि दल के 9 मौजूदा विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द बड़ा फैसला लिया जाएगा। 'अपना मोर्चा' फिलहाल एनडीए का हिस्सा है लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के रवैये के आधार पर यह समीकरण बदल भी सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के हिस्से की विधानसभा व लोकसभा सीटों पर दावेदारी को लेकर भी मोर्चा मंथन करेगा। मोर्चा ने यह भी ऐलान किया कि वह राज्य भर में 'सवाल पूछो, सच जानो' यात्रा निकालेगा, ताकि कुर्मी, किसान और कमेरा समाज को बताया जा सके कि उनके संघर्ष और वोट से सत्ता तक पहुंचने वाले लोगों ने किस तरह समाज को ठगा।

प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि किस तरह अनुप्रिया पटेल और उनके पति ने लगातार वरिष्ठ नेताओं, पुराने पदाधिकारियों और विधायकों को दरकिनार किया। 2017 में सत्ता में हिस्सेदारी मिलते ही आशीष पटेल को पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया और वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया गया। जहानाबाद से विधायक जय कुमार सिंह 'जैकी', सेवापुरी से विधायक नील रतन पटेल और सपा में गए आर.के. वर्मा जैसे कुर्मी नेताओं को योजनाबद्ध तरीके से हाशिए पर डाल दिया गया।

पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता डॉ. रविन्द्रनाथ द्विवेदी, चौधरी नेपाल सिंह कसाना और बलिहारी पटेल जैसे संस्थापक नेताओं को नजरअंदाज कर पार्टी को पूरी तरह परिवार केंद्रित बना दिया गया। यहां तक कि दल में महापुरुषों की जयंती तक मनाना प्रतिबंधित कर दिया गया। पत्रकारों, सामाजिक संगठनों और रिटायर्ड अफसरों के खिलाफ भी साजिशें रची गईं और ट्रोलिंग करवाई गई।

मोर्चा के संयोजक बृजेंद्र प्रताप सिंह पटेल की अगवाई में कई पदाधिकारियों ने किया शंखनाद।

बोले ब्रजेंद्र प्रताप सिंह

यह सिर्फ राजनीतिक नहीं सामाजिक आंदोलन है

ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक नहीं सामाजिक आंदोलन है।उन्होंने कहा कि कुर्मी समाज अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी कोशिश है कि समाज को धोखे से निकाला जाए और उसके सामने पूरा सच रखा जाए। उन्होंने कहा कि 'अपना मोर्चा' की अगली बैठक 2 जुलाई को लखनऊ के फरीदी नगर स्थित कुर्मी क्षत्रिय भवन में होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। प्रेस वार्ता में अपना दल (बलिहारी गुट) के अध्यक्ष धर्मराज पटेल, राष्ट्रीय जनसरदार पार्टी के अध्यक्ष हेमंत चौधरी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य अरविंद सिंह पटेल, किसान नेता केदारनाथ सचान, अपना दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बच्चा सिंह पटेल और किसान-नवजवान संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह पटेल भी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अब कुर्मी समाज अपना नया नेतृत्व तैयार करेगा जो ज़मीन से जुड़ा हो, न कि सत्ता की दलाली करने वाला।

अपना दल एस का साथ छोड़ने वाले बुनियादी नेता

- प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आरके वर्मा
- श्री धर्म राज पटेल, राष्ट्रीय महासचिव
- श्री नील रतन पटेल
- श्री पटेल अमर सिंह चौधरी
- श्रीमती मिथलेश कटियार
- श्री पकौड़ी लाल
- श्री हरि राम
- श्री चन्द्र प्रताप पटेल
- श्री ज्ञानेंद्र पटेल ज्ञानू
- पूर्व सांसद डॉ. आसकरन संखवार
- श्री महेश बाल्मीकि पूर्व विधायक
- पूर्व सांसद श्रीमती सारिका सिंह बघेल
- चौधरी नैपाल सिंह कसाना
- श्री हेमंत चौधरी
- पूर्व विधायक श्री राज कुमार पाल
- श्री केदार नाथ सचान
- श्री अवध नरेश वर्मा
- श्री डॉ. राघवेंद्र प्रताप सिंह
- श्री डॉ. राजेश सिंह
- श्री सुरेश यादव प्रदेश सचिव
- श्री अरविंद शर्मा प्रदेश प्रवक्ता
- श्री बौद्ध अरविंद सिंह पटेल
- जस्टिस एचसी वर्मा
- श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पटेल
- डॉ. रविंद्र नाथ द्विवेदी
- श्री रजनीश तिवारी
- श्रीमती कृष्णा पटेल

डॉक्टर्स डे पर छात्रों ने जताया आभार

» डॉक्टर्स डे पर छात्रों ने जताया आभार

» अस्पताल जाकर दिए धन्यवाद कार्ड

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। मकनपुर स्थित आरपीएस गौरव इंटरनेशनल स्कूल में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर छात्रों ने श्रीश हॉस्पिटल पहुंचकर वहां कार्यरत डॉक्टरों को धन्यवाद कार्ड भेंट किए और उनके निःस्वार्थ सेवा भाव के लिए सम्मान प्रकट किया। छात्रों ने अपने हाथों से सुंदर कार्ड बनाकर डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना सभा में डॉक्टर्स डे के महत्व को समझाने के साथ हुई, जहां शिक्षकों ने डॉक्टरों को समाज का देवदूत बताया। बच्चों को यह बताया गया कि कैसे डॉक्टर दिन-रात मानव सेवा में लगे रहते हैं।

प्रधानाचार्य लकी जैन ने कहा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे समाज के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बनें।निदेशक आरती कटियार ने कहा ऐसे अवसर बच्चों में सेवा और सम्मान की भावना को मजबूत करते हैं।छात्रों के इस प्रयास ने जहां डॉक्टरों को भावुक किया,वहीं समाज को यह संदेश भी दिया कि कृतज्ञता जताना भी एक शिक्षा है।

यह पहल न केवल प्रेरणादायक रही बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में भी एक सराहनीय कदम थी।

इमाम हुसैन की शहादत को किया गया याद

» अखाड़े के मैदान में मजलिस का किया गया आयोजन

» हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद के लगे नारे

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)।मोहल्ला खानजादा के ऐतिहासिक अखाड़े के मैदान में सोमवार शाम को इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की कुर्बानी की याद में मजलिस का आयोजन किया गया। बताया गया कि यह मजलिस पिछले कई सालों से लगातार इसी मैदान में होती आ रही है, जहां यह परंपरा अब भी कायम है।कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज आलम मदारी ने कुरआन पाठ से की। इसके बाद अनीस हुसैन, खुशनवाज कादरी, खुश्तर कादरी और आतिफ हुसैनी ने इमाम हुसैन की शान में भावपूर्ण नज़्में पेश कीं।मुख्य तकरीर मौलाना राकिम कादरी ने दिया। उन्होंने कर्बला के बारे में जानकारी देते हुए, इमाम हुसैन की कुर्बानी और इंसाफ और सच्चाई के लिए उनके संघर्ष को विस्तार से बताया। मजलिस का समापन तनवीर साबरी ने सलाम पढ़कर किया।इस मौके पर अखाड़े के प्रमुख कुदरत उल्ला, नसरुल्ला, जमील अंसारी, अनवार अली, बबलू वारसी, रईस अंसारी,क़व्वाल नसीम अंसारी फैजान बेग, फैज़ मोहम्मद, अलीम बागुल और मुस्तवीन समर बिल्हौरी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

नगर आयुक्त ने किया मियांवाकी पद्धति से वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। वन महोत्सव सप्ताह (1 से 7 जुलाई) के दृष्टिगत नगर आयुक्त श्री सुधीर कुमार ने सोमवार को जलकल विभाग मुख्यालय परिसर में मियांबाकी पद्धति से किए गए वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पर्यावरण अभियंता श्री भास्कर भी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने निर्देश दिए कि मियांबाकी पद्धति से वृहत क्षेत्रफल में वृक्षारोपण का प्रस्ताव तैयार कराया जाए तथा अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाए जाएं।

उन्होंने पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करने को भी कहा।पर्यावरण अभियंता ने बताया कि यह जापानी पद्धति जल संरक्षण और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में सहायक है तथा इससे शहर के पर्यावरण को स्थायी लाभ मिलेगा।नगर निगम द्वारा वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत जी.टी. रोड ग्रीन बेल्ट, एल.एम.एल. चौराहा, बर्रा बाईपास से रामा देवी मार्ग और बिनगवा स्थित एस.टी.पी. के पास वृक्षारोपण कराया जा रहा है।नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में मियांबाकी पद्धति से वृक्षारोपण को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा।

केडीए केयर टेकर: कार्य पहले, टेंडर बाद में

» केडीए मुख्यालय के पोर्टिको में फार सीलिंग कार्य और रिकार्ड रूम मरम्मत कार्य पहले ही हो चुका, अब निकाला गया टेंडर

» केडीए के केयर टेकर अनुभाग में चल रही बडी धांधली

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण में अफसरों की उदासीनता के चलते व्यवस्थाएं बेपटरी हो चली हैं। केडीए के केयर टेकर अनुभाग में नियम-कायदों को ताकपर रखकर चहेते ठेकेदारों से कार्य पहले कराकर खानापूर्ति के लिए टेंडर बाद में निकाला जा रहा है। इससे योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टालरेंस नीति को पलीता लगा रहा है और विभागों में पारदर्शिता और सुचिता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार केडीए के केयर टेकर अनुभाग में हर माह लाखों रूपयों के भुगतान विभिन्न मदों पर किए जा रहे हैं लेकिन सरकारी नियमों को दरकिनार कर चहेतों को भुगतान सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। ताजा इनपुट के मुताबिक केडीए मुख्यालय के पोर्टिको में फाल सीलिंग लगाने का कार्य 3 माह पूर्व हो चुका है लेकिन 2 जुलाई 2025 को 2 लाख 45 हजार रूपए का टेंडर निकाला गया है। जब कि पोर्टिको की मरम्मत के नाम पर सिर्फ फॉलसीलिंग टांग दी गई हैं, जब कि छत की सरिया भी दिख रही थीं उनपर प्लास्टर करना भी जरूरी नहीं समझा गया।

कुछ दिन बाद फिर मरम्मत की फाइल तैयार होगी। इसी तरह से केडीए के रिकार्ड रूम की रंगाई पुताई और मरम्मत के नाम पर 2 लाख 99 हजार रूपए का टेंडर निकाला गया है,

विभागीय सूत्रों का दावा है कि यह कार्य भी पहले ही हो चुका है। इस तरह से केयर टेकर मरम्मत और आपूर्ति के नाम पर फर्जी फाइलें बनाकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है।

सफाई सुपरवाइजर बन गया ठेकेदार

केडीए के केयर टेकर अनुभाग में किस तरह से खेल चल रहा है। यह समझिए कि केडीए में सफाई सफाई सुपरवाइजर को ठेकेदार बनाकर फाइलें तैयार कराकर भुगतान किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई और ऐसे ठेकेदार जो कि पहले से ही सेट हैं उनको ही काम दिया जाता है। टेंडर और कुटेशन प्रक्रिया तो सिर्फ रस्म अदायगी भर है।

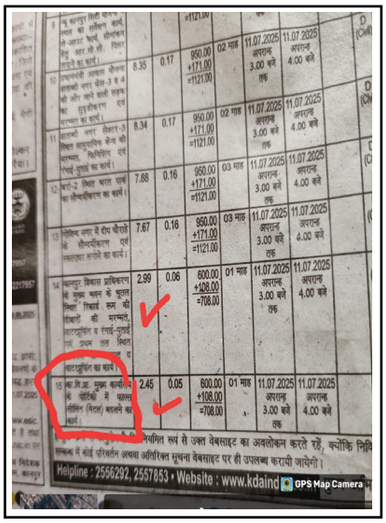

केयर टेकर नहीं संभाल पा रहे अतुल राय!

केडीए में केयर टेकर प्रभारी के तौर पर जब से अनुभवहीन एई अतुल राय की तैनाती की गई है तब से लगातार सवाल उठ रहे हैं।

कामकाज में पारदर्शिता नहीं और मनचाहे ढंग से फाइलों को बनाकर कार्य कराए जाने से धांधली की आशंका बनी हुई है। अतुल राय के कार्यकाल की जांच कराई जाए तो बडे बडे खुलासे हो सकते हैं।

हरे पेड़ों का कत्लेआम, लकड़ी माफिया फरार

प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। चौबेपुर ब्लॉक अंतर्गत राय गोपालपुर ग्राम पंचायत के गोविंदेपुर गांव में हरे-भरे पेड़ों की बेरहमी से कटाई कर दी गई। पिपरियन निवासी अरविंद नामक लकड़ी माफिया पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मनोज सविता के आम के बाग में दर्जनों हरे पेड़ अवैध रूप से काट दिए।

» राय गोपालपुर पंचायत के आम के बाग में दर्जनों पेड़ काटे, ग्रामीणों से की गई अभद्रता

» वन विभाग हरकत में, डीएफओ बोलीं मामले में होगी सख्त कार्रवाई, दर्ज होगी एफआईआर

जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तो माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ अभद्रता और धमकियां दीं। इस घटना की सूचना जैसे ही क्षेत्रीय पत्रकारों तक पहुँची, वे मौके पर पहुंचे लेकिन अरविंद और उसके साथी तब तक फरार हो चुके थे।

पत्रकारों ने तुरंत टिकरा पुलिस चौकी को सूचना दी, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।सूत्रों की मानें तो अरविंद एक शातिर लकड़ी तस्कर है, जो लंबे समय से हरे पेड़ों की चोरी कर लकड़ी अवैध रूप से बेचने का धंधा करता आ रहा है।गांव वालों ने यह भी आरोप लगाया है कि इस अवैध कारोबार में वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है, जिन्हें नियमित कमीशन दिया जाता है।दैनिक स्वराज इंडिया की टीम ने जब इस मामले पर कानपुर के जिला वन अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और अरविंद के खिलाफ वन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

बिकरू की वो रात आज भी जिंदा है जब खाकी पर गोलियों की बौछार हुई

शिवांग अग्निहोत्री/स्वराज इंडिया

कानपुर। 1 जुलाई 2020 की वो रात सिर्फ एक तारीख नहीं थी वो था एक ऐसा खौफनाक मंजर, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। बिकरू गांव की उन्हीं गलियों में, विकास दुबे नाम के दुर्दांत अपराधी ने पुलिस टीम पर सुनियोजित हमला कर आठ जांबाज़ पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था।

इस घटना के पांच साल पूरे होने पर, दैनिक स्वराज इंडिया के डिजिटल पैनल की टीम रात लगभग 11 बजे बिकरू गांव पहुंची उसी घड़ी, जब पांच साल पहले पुलिस के खून से ज़मीन लाल हुई थी। संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री ने वहां से एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जिसमें उस रात की यादें आज भी जिंदा नजर आईं।गांव के रास्तों में सन्नाटा, दीवारों पर पसरा खौफ, और लोगों के चेहरों पर छपी चुप्पी यह सब उस नरसंहार की स्थायी छाप है।गांव के लोग आज भी मीडिया से बात करने में झिझकते हैं, और रात होते ही बिकरू की गलियां फिर से वीरान हो जाती हैं।

1 जुलाई 2020 को हुए नरसंहार को स्वराज इंडिया ने 5 साल बाद फिर से जिंदा किया

गांव में अब भी पसरा है खामोश डर, बिकरू की गलियां कुछ नहीं कहना चाहतीं

वो जो ड्यूटी पर निकले थे और अमरता की ओर चले गए

देवेंद्र मिश्रा– एक सीधा, सख्त और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी। बिल्हौर के सीओ के तौर पर उन्होंने बिकरू गांव में अपराध के बढ़ते खतरे को पहचान लिया था। पर वह रात उनकी अंतिम ड्यूटी बन गई। उनके साहस ने दिखा दिया कि एक अधिकारी आखिरी सांस तक डटा कैसे रहता है।

महेश यादव– शिवराजपुर थाने के एसओ। जो टीम को लीड कर रहे थे, वही सबसे पहले गोली की ज़द में आए। उनके नेतृत्व में गई टीम को धोखे से घेर लिया गया, और उन्होंने गोलियों के बीच भी पीछे हटना नहीं चुना।

नेबूलाल– एक ऐसा नाम, जो अक्सर शांत रहता था, लेकिन काम में सबसे आगे। उस रात उन्होंने अपने साथियों की रक्षा करते हुए प्राण गंवाए।

अनुप सिंह– जवान कांस्टेबल थे, जिनकी उम्र शायद सबसे कम थी इस टीम में। लेकिन साहस उम्र नहीं देखता – उन्होंने जान की परवाह किए बिना टीम के साथ मोर्चा लिया।

सुल्तान सिंह– जिनके गांव में लोग आज भी उनकी बहादुरी की कहानियां बच्चों को सुनाते हैं। उन्होंने आखिरी वक्त तक डटे रहकर अपने साथियों को कवर देने की कोशिश की।

राहुल कुमार– एक युवा सिपाही, जिनके घरवालों को लगा था कि वो एक सामान्य गश्त पर गए हैं। पर उन्हें क्या पता था कि वो अंतिम गश्त होगी वो जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी।

जितेंद्र पाल सिंह–उनका शांत स्वभाव और अनुशासन हर किसी को याद है। उस रात उन्होंने किसी को अकेला नहीं छोड़ा, और आखिरी सांस तक साथ निभाया।

बबलू कुमार– उन पर गोलियों की बौछार हुई, लेकिन उन्होंने अपनी पोज़िशन नहीं छोड़ी। साथी जवानों को बचाने की कोशिश में खुद शहीद हो गए।

इन सभी ने कर्तव्य की परिभाषा को उस रात बदल डाला। ये सिर्फ पुलिसकर्मी नहीं थे ये वो दीवारें थीं, जो समाज और अपराध के बीच खड़ी थीं।बिकरू की गलियों में भले आज सन्नाटा हो, लेकिन इन शहीदों के नाम हर उस सांस में ज़िंदा हैं, जो कानून के लिए जीती है। स्वराज इंडिया की ये रिपोर्ट उन सबको समर्पित है जो वापस नहीं आए, लेकिन हमेशा रहेंगे।

अवैध शराब से भरी एंबुलेंस को आबकारी और पुलिस ने पकड़ा

» दो तस्कर गिरफ्तार,लाखों का माल बरामद

कानपुर/फतेहपुर। फतेहपुर जिले में हरियाणा से लाखों की अवैध अंग्रेजी शराब लेकर बिहार जा रही एक एंबुलेंस को थरियांव पुलिस और आबकारी टीम ने पकड़ा है। टीम ने दो शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है। थरियांव थानाध्यक्ष आलोक पांडेय, आबकारी निरीक्षक उपेंद्र शुक्ला ने अपनी टीम के साथ हाईवे में पूर्वी बाईपास के पास चेकिंग के दौरान शराब से भरी एक एंबुलेंस को पकड़ा।

टीम ने एंबुलेंस से हरियाणा राज्य की अवैध अंग्रेजी शराब की 75 पेटियां बरामद की हैं। गाड़ी समेत शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। संयुक्त टीम ने दो शराब तस्कर मिलन कुमार चौधरी निवासी कुमारगंज सुपौल और जितेंद्र कुमार निवासी भारतीय नगर सहरसा बिहार को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष आलोक पांडेय ने बताया कि आरोपी शराब की तस्करी करते है।

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरियाणा से शराब ले जाकर बिहार में ऊंचे दामों पर शराब की बिक्री करते हैं।

आरोपियों के कब्जे से 666.36 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब, एक एंबुलेंस, दो एंड्राइड मोबाइल फोन और 1250 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

सम्पादकीय

कमियां दूर कर लाभ का हो विस्तार

इसमें दो राय नहीं कि पिछले एक दशक में प्रौद्योगिकी ने आम भारतीय के जीवन को सहज-सरल बनाने में निर्णायक भूमिका निभायी है। आज तमाम तरह की सुविधाओं को हासिल करने के लिये उसे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अनेक सेवाएं एक क्लिक के साथ उसकी मुट्ठी में होती हैं। दरअसल, डिजिटल इंडिया की महत्वाकांक्षी पहल नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। जिसका मकसद रोजाना व्यवहार में सामने आने वाली जटिलताओं को दूर करके जीवन को आसान बनाना था। निस्संदेह, पिछले एक दशक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने कई प्रकार से नागरिकों को सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभायी है। विशेष रूप से डिजिटल भुगतान आज पूरे देश में अपरिहार्य हो गए हैं। इससे जुड़े आंकड़े पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। इस वर्ष अप्रैल में लगभग 25 लाख करोड़ रुपये के यूपीआई लेन-देन किए गए हैं।

इन यूपीआई लेनदेन की संख्या करीब 1,860 थी। वर्ष 2023 में भारत ने वैश्विक रीयल-टाइम लेनदेन का 49 फीसदी हासिल किया। जिसमें 46 करोड़ लोग और 6.5 करोड़ व्यापारी यूपीआई का उपयोग कर रहे थे। निस्संदेह, शासन के विभिन्न क्षेत्रों में भी डिजिटल उपयोग में खासी प्रगति हुई है। जिससे व्यवस्था अधिक पारदर्शी और नागरिकों के हितों के अनुकूल हो गई है। इस डिजिटल क्रांति के चलते स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिंग और अन्य सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच आसान हुई है। डिजिटल क्रांति से जुड़ी तमाम चुनौतियों के अलावा अभी देश में डिजिटल डिवाइड की समस्या बनी हुई है। जिसे यथाशीघ्र पाटने की जरूरत है। हालांकि, इस दिशा में आशातीत प्रगति भी हुई है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने के लिये चरणबद्ध प्रयासों की सख्त जरूरत है। यह चुनौती ग्रामीण भारत में अधिक नजर आती है। जहां इंटरनेट सेवाओं और मोबाइलों की पहुंच शहरों के मुकाबले कम है। जाहिर है, जब देश के हर व्यक्ति तक डिजिटल क्रांति का लाभ पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा, इस क्रांति के लक्ष्य अधूरे ही रहेंगे।

निश्चित रूप से देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग आदि सेवाओं में जो व्यापक सुधार आया है, उसका लाभ हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर देश में डिजिटल डिवाइड की खाई को पाटने की दिशा में मिशन के रूप में प्रयास जारी हैं। लेकिन हाल में हुए कुछ सर्वेक्षणों के निष्कर्ष चिंता बढ़ाने वाले हैं। इसमें शामिल व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण - दूरसंचार, 2025 का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के केवल 57.2 फीसदी स्कूलों में कार्यात्मक कंप्यूटर ही उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी ओर 53.9 प्रतिशत स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। देश के विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारत नेट परियोजना के तहत कुल 6.55 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिये लक्षित किया जाना था, लेकिन अभी तक उसमें दो-तिहाई गांवों को कवर किया जाना अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर देश की इस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने बीएसएनएल की दुर्दशा को भी उजागर किया है, जो एक के बाद एक पुनरुद्धार पैकेज मिलने के बावजूद टेलीकॉम क्षेत्र की निजी कंपनियों के खिलाड़ियों से पीछे है। निस्संदेह, मोदी सरकार के पास डिजिटल इंडिया की प्रगति के लिये अपनी पीठ थपथपाने के लिये कई कारण हैं, लेकिन उसे कमियों और अंतरालों पर ध्यान देने की सलाह दी जाएगी। निश्चित रूप से डिजिटल पारिस्थितिकीय तंत्र के भीतर व्याप्त असमानताओं को दूर किए बिना विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करना है।

बड़े धार्मिक आयोजनों का वैज्ञानिक प्रबंधन जरूरी

विश्वनाथ सचदेव

त्रिभाषा फार्मूले का विरोध करने वालों को भी यह समझना होगा कि आवश्यकता इसके ईमानदार क्रियान्वयन की है। वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में इस फार्मूले को स्वीकारा गया था। तब यह कहा गया था कि तीसरी भाषा के रूप में उत्तर वाले दक्षिण की किसी भाषा को सीखेंगे और दक्षिण वाले उत्तर की भाषा हिंदी को। पर उत्तर वालों ने यहां ईमानदारी नहीं दिखाई। उन्होंने तीसरी भाषा के रूप में दक्षिण भारत की किसी भाषा के बजाय मुख्यत: संस्कृत को चुना।

आपातकाल में हमारे संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गये थे- पहला 'पंथ निरपेक्षता' और दूसरा समाजवाद। संविधान जब तैयार किया जा रहा था तब भी इन शब्दों की आवश्यकता की चर्चा हुई थी, पर तब हमारे संविधान निर्माताओं ने यह माना था कि यह दोनों विचार संविधान में अन्यत्र स्पष्ट रूप से जुड़े हुए हैं, अत: इन्हें अलग से प्रस्तावना में जोड़ना आवश्यक नहीं है। जब आपातकाल के दौरान इन्हें जोड़ा गया तो तर्क यह दिया गया था कि यह दोनों विचार प्रमुखता के साथ रेखांकित होने चाहिए। संविधान के 42वें संशोधन से इसे रेखांकित कर दिया गया।

बाद की जनता पार्टी की सरकार ने भी इस बात को मान लिया। पचास साल बाद यह विवाद फिर सिर उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को यह लग रहा है कि इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना से हटा कर अब अपनी विचारधारा को संविधान में शामिल किया जा सकता है। और यदि संख्या की दृष्टि से फिलहाल संविधान में प्रयुक्त संशोधन नहीं हो सकता तो भी देश में अपने विचार के समर्थन में वातावरण बनाने का यह अच्छा मौका है।

ऐसी ही एक कोशिश महाराष्ट्र में भी हो रही है- राज्य की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र की नयी शिक्षा-नीति को लागू करने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए यह निर्णय लिया था कि राज्य में त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाये। इस फार्मूले के अनुसार राज्य के स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के बच्चों को मराठी और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाई जानी थी। विपक्ष, विशेषकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को, सरकार के इस निर्णय का विरोध करके अपनी जमीन को मज़बूत करने का अवसर दिखाई दिया। उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी कि उनकी पार्टी इस निर्णय को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगी। लगभग दो दशक पहले बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर अपना स्वयं का राजनीतिक दल बनाने वाले उनके भतीजे राज ठाकरे को भी इस स्थिति में एक अवसर दिखाई दिया और उन्होंने भी घोषणा कर दी कि राज्य सरकार की ‘मराठी विरोधी नीति’ को लागू नहीं होने दिया जायेगा। कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी भी ठाकरे बंधुओं के आह्वान के साथ जुड़ गयीं। एक बार फिर राज्य में मराठी अस्मिता के नाम पर माहौल बनने लगा। स्थिति को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि पहली से पांचवीं तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जायेगी, यदि बच्चे किसी अन्य भाषा को पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए स्कूलों में इसकी व्यवस्था की जायेगी, बशर्ते किसी अन्य भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम से कम बीस हो। सरकार को लगा था कि इस घोषणा से स्थिति संभल जायेगी। पर ऐसा हुआ नहीं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठे) और राज ठाकरे की मनसे, दोनों किसी भी कीमत पर इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तय हुआ कि पांच जुलाई को राज्य का समूचा विपक्ष मराठी भाषा और मराठी अस्मिता की रक्षा के नाम पर केंद्र के निर्देश से काम करने वाली महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के विरोध में आंदोलन करेगा।बाजी हाथ से निकलते देख कर राज्य सरकार ने हिंदी की पढ़ाई वाला अपना कदम वापस लेने का निर्णय किया। अब एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है जो राज्य के स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूले को लागू किये जाने के बारे में अध्ययन करके अपना सुझाव देगी।

पहाड़ों की संवेदनशीलता को समझना भी जरूरी

हिमाचल में जल-रौद्र

पंकज चतुर्वेदी

गंभीरता से देखें तो इन आपदाओं को बुलाने में इन्सान की भूमिका भी कम नहीं है। दुनियाभर के शोध कह रहे थे कि हिमालय पर्वत जैसे युवा पहाड़ पर पानी को रोकने, जलाशय बनाने और सुरंगें बनाने के लिए विस्फोटक के इस्तेमाल के अंजाम अच्छे नहीं होंगे।

सुंदर, शांत, सुरम्य हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कुदरत ने रौद्र रूप धारण किया है। छोटे से राज्य का बड़ा हिस्सा अचानक आई तेज बरसात और जमीन खिसकने से त्रस्त है तो जहां आपदा आई नहीं वहां के लोग भी आशंका में जी रहे हैं। आषाढ़ में मानसून की पहली बौछार के साथ ही कई जिलों, विशेषकर कुल्लू और धर्मशाला में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। इससे कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। कुल्लू और धर्मशाला जिलों में अनेक जगह बादल फटने की घटनाएं हुईं, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और अनेक लापता हैं। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कांगड़ा के खनियारा क्षेत्र में इंदिरा हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास प्लैश फ्लड में 20 मजदूर बह गए, जिनमें से कुछ के शव बरामद हुए हैं, बाकी की तलाश जारी है।

कुल्लू की सेंज घाटी में तमाम पर्यटक फंसे हुए हैं। यहां बादल फटने से एक ही परिवार के तीन लोग बह गए। धर्मशाला-चतरो-गगल मार्ग और अपर शिमला क्षेत्र में त्यूणी-हाटकोटी मार्ग जैसे कई प्रमुख मार्ग भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अभी तो सावन-भादों आगे हैं। दुखद यह कि वैज्ञानिकों द्वारा इस बारे में दी गई ढेर सारी चेतावनियां फाइलों में बंद हैं। सरकारी महकमे अपने ढर्रे पर काम कर रहे हैं जबकि पहाड़ जलवायु परिवर्तन के विविध कुप्रभावों से ग्रस्त हैं।इसी साल 14-15 फ़रवरी को आईआईटी, बॉम्बे में सम्पन्न दूसरे इंडियन क्रायोस्फीयर मीट में आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिकों ने एक शोधपत्र प्रस्तुत कर बताया था कि हिमाचल राज्य का 45 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। 5.9 डिग्री और 16.4 डिग्री के बीच औसत ढलान वाले और 1,600 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र विशेष रूप से भूस्खलन और बाढ़ दोनों के लिए प्रवण हैं। इस बैठक में दुनियाभर के लगभग 80 ग्लेशियोलॉजिस्ट, शोधकर्ता और वैज्ञानिक शामिल हुए। इतनी स्पष्ट चेतावनी के बावजूद न समाज चेता और न ही सरकार।नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इसरो द्वारा तैयार देश के भूस्खलन नक्शे में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों को बेहद संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। देश के कुल 147 ऐसे जिलों में संवेदनशीलता की दृष्टि से मंडी को 16वें स्थान पर रखा गया है। यह आंकड़ा और चेतावनी फाइल में सिसकती रह गई।

यही हाल शिमला का हुआ जिसका स्थान इस सूची में 61वें नम्बर पर दर्ज है। प्रदेश में 17,120 स्थान भूस्खलन संभावित क्षेत्र अंकित हैं, जिनमें से 675 बेहद संवेदनशील मूलभूत सुविधाओं और घनी आबादी के करीब हैं। भूस्खलन की दृष्टि से किन्नौर जिला को सबसे खतरनाक माना जाता है। बीते साल भी किन्नौर के बटसेरी और न्यूगलसरी में दो हादसों में ही 38 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद किन्नौर जिला में भूस्खलन को लेकर भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के विशेषज्ञों के साथ-साथ आईआईटी, मंडी व रुड़की के विशेषज्ञों ने अध्ययन किया है।हिमाचल सरकार की डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल द्वारा प्रकाशित एक 'लैंडस्लाइड हैज़ार्ड रिस्क असेसमेंट' अध्ययन ने पाया कि बड़ी संख्या में हाइड्रोपावर स्थल पर धरती खिसकने का खतरा है। लगभग 10 ऐसे मेगा हाइड्रोपावर प्लांट, स्थल मध्यम और उच्च जोखिम वाले भूस्खलन क्षेत्रों में स्थित हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सर्वेक्षण कर भूस्खलन संभावित 675 स्थल चिन्हित किए हैं।

बिल्हौर में धूमधाम से मनाया गया सपा मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन

» दर्जनों स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

» वर्ष 2027 में सत्ता में वापसी का लिया संकल्प

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रचना सिंह गौतम और विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सपा सरकार की पूर्व उपलब्धियों पर चर्चा की गई। रचना सिंह गौतम ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो तानाशाही सरकार को चुनौती दे सकती है।

वहीं विनय यादव ने विश्वास जताया कि समाजवादी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसका असर वर्ष 2027 के चुनाव में साफ दिखाई देगा। इसी क्रम में अरौल में भंडारे का आयोजन किया गया,जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कस्बे में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष (कानपुर ग्रामीण) निर्भय सिंह यादव के आवास पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान पीडीए मॉडल पर भी विस्तृत चर्चा की गई। निर्भय सिंह यादव ने अपील की कि सभी कार्यकर्ता समाज के हर वर्ग में जाकर लोगों को जागरूक करें और उन्हें बताएं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।इस अवसर पर सपा नेता विनय कोरी, असद, आशीष चटरू सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मकनपुर में वृक्षारोपण कर सपा मुखिया का जन्मदिन मनाया

समाजवादीपार्टी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव शादान शिकोह जाफरी और प्रदेश सचिव वासिफ हुसैन ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण किया। इसके पश्चात केक काटा गया और उनके दीर्घायु होने की कामना की गई।इस अवसर पर अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मुकीम खान, शरफ अली समेत अनेक समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर पार्टी की मजबूती और अखिलेश यादव के नेतृत्व में आगामी चुनावों की सफलता का संकल्प भी लिया।

जिले में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, भगत सिंह एसीएम प्रथम

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। जिले में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेयबदल हुआ है। जिले में तबादला हो चुके राजेश कुमार, रामानुज और सत्यप्रकाश को डीएम ने रिलीव कर दिया है।

अमरोहा से आए भगत सिंह को एसीएम प्रथम बनाया गया है। तहसीलदार घाटमपुर अनुभव चंद्रा को लंबे समय से खाली तहसीलदार बिल्हौर के पद पर भेजा गया है। जिले में नई आई नायब तहसीलदार अंकिता पाठक को प्रभारी तहसीलदार घाटमपुर बनाया गया है। जिले में आए नायब तहसीलदार सृजन कुमार को तहसील सदर, नायब तहसीलदार घाटमपुर राजेश कुमार तिवारी को सदर, नायब तहसीलदार सदर भव्या उपाध्याय को नायब तहसीलदार भूलेख अधिष्ठान मुख्यालय और प्रभारी तहसीलदार बिल्हौर चंद्र प्रकाश राजपूत को नायब तहसीलदार बिल्हौर बनाया गया है।

डील शब्द ने माननीय को क्यों कराया बैड फील

डील कथा

हो सकता है उससे हमारी डील न हो फिर भी हम उसे अच्छे से डील करेंगे यह उदाहरण है उन डील शब्दों का जो पाठक जी ने समझा और जिसे आईपीएस ने बोला ।

डील शब्द नकारात्मक तो नहीं है और ना ही यह शब्द चस्पा होने से किसी की छवि पर विपरीत असर पड़ता है। फिर भी डील शब्द ने बवंडर ला दिया। एक कारण यह भी हो सकता है दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस प्रकार डील डील की रट लगाई है उससे इस शब्द की वैल्यू भारतीयों की नजर में गिर गई हो।

वैसे अब यह राज राज नहीं रहा कि एमएलसी अरुण पाठक को आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा ने कहां पर डील किया था! पता तो आपको भी चल गया होगा? वैसे आपको बता दें तमाम विवादों की तरह इस विवाद का भी योगी दरबार तक पहुंचना तय है।

निर्मल तिवारी / स्वराज इंडिया

कानपुर । शुभचिंतकों को लग रहा है पाठक साहब का समय कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। मृदुभाषी, विनम्र, मिलनसार हमेशा लो प्रोफाइल रहकर लोगों से जुड़े रहने वाले और एक ही मुलाकात में व्यक्ति को अपना मुरीद बना लेने वाले एमएलसी अरुण पाठक हमेशा विवादों से दूर ही रहे हैं। लेकिन अचानक 30 दिन के अंदर दो बार वह विवादों के दलदल में फंसते नजर आए। वैसे बहुत से नेता लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ विवादित करते रहते हैं। लेकिन एमएलसी अरुण पाठक इस प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञ नहीं हैं। बावजूद इसके एक महीने के अंदर दो बार उनका विवादों में घिरना लोगों को अचंभित कर रहा है। पहले डीएम–सीएमओ विवाद में सीएमओ के पक्ष में चिट्ठी लिखने के बाद वह विवादों में घिरे। लेकिन बात आगे बढ़ने के पहले ही उन्होंने स्वयं को न्यूट्रल कर विवाद से बचा लिया और अब एडीसीपी के साथ हुई हॉट टॉक ने उन्हें एक बार फिर नकारात्मक चर्चा में ला दिया है। सोशल मीडिया के जमाने में दोनों पक्षों के चाहते हुए भी विवाद का अंत सरलता से हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इस विवाद में भी जल्द से जल्द इतिश्री होती नहीं दिख रही है।

सारगर्भित प्रसंग

डील शब्द के चक्कर में ऑपरेशन सिंदूर कप के दौरान कानपुर से पूरे देश में फैले रायते का चटखारा तो आप ले चुके होंगे। बात तो यह भी उसी संदर्भ में है। लेकिन उससे पहले इस ऑपरेशन सिंदूर कप के मैच से जुड़ा एक प्रसंग आपके साथ साझा करता हूं। सांसद इलेवन की तरफ से चौथा ओवर फेंक रहे विधायक सोमेंद्र तोमर की पांचवी बॉल खेलने के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने अंपायर से नो बॉल की अपील की और अंपायर ने बिना एक पल की देरी किए नो बाल घोषित भी कर दिया। कारण था नियमानुसार पावर प्ले में मात्र दो ही खिलाड़ी सर्कल से बाहर रह सकते हैं जबकि सांसद एकादश की ओर से तीन खिलाड़ी उस समय सर्कल के बाहर फील्डिंग कर रहे थे। कमेंटेटर ने टिप्पणी की, शायद सांसद एकादश के खिलाड़ी सोच रहे होंगे कौन सा यह इंटरनेशनल मैच है, एक दोस्ताना मैच ही तो है, नियमों में थोड़ी बहुत ढील तो चलती है! लेकिन नियम तो नियम है। नियमानुसार यह नो बाल है। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार खेल के मैदान में एक दोस्ताना मैच में भी कितनी गंभीरता से नियमों को फॉलो कर और करा रहे थे, यह प्रसंग उसकी बानगी है।

कल इसी विषय पर जब कानपुर के कुछ भाजपाइयों के साथ चर्चा की गई तो कई भाजपाइयों ने तर्क दिया कि यह कोई अंतरराष्ट्रीय मैच तो था नहीं! कानपुर के सांसद जी मैच करा रहे थे। दोस्ताना मैच था। क्रिकेट बोर्ड के नियमों के पालन का दबाव भी नहीं था। साथ ही मौसम भी प्रतिकूल था तो नियम में थोड़ी ढील तो बनती है। नियमों को लेकर प्रशासन की सोच और अन्य की सोच विपरीत ध्रुव पर नजर आती है जो उस दिन के टकराव का तात्कालिक कारण हो सकती है ।

सहज शब्द था डील या फिर व्यंग बाण

डील शब्द का उपयोग जानबूझकर व्यंग्यात्मक लहजे में किया गया या उससे पहले एडीसीपी द्वारा "वेपन जानते हैं ना आप" वाले कथन के चलते एमएलसी अरुण पाठक ने डील शब्द को व्यंगात्मक माना। यह बात दीगर है कि एडीसीपी

अंजलि विश्वकर्मा ने डील शब्द के माध्यम से जो व्यंग बाण छोड़ा उसे सधे हुए राजनेता की तरह एमएलसी अरुण पाठक ने लपक कर उसे प्रश्न उत्सर्जक बाण बनाकर एडीसीपी की तरफ ही चला दिया। कानपुर में ही नहीं डील शब्द ने सोशल मीडिया के माध्यम से देश भर में धमाल मचा दिया है। जिसमें नजर आ रहे दोनों व्यक्तियों की लैंग्वेज के साथ ही बाडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रही है। ऐसा लग रहा है एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा के इस एक शब्द ने पाठक साहब को आहत तो कर दिया था। शायद उन्हें कुछ याद दिला दिया या कहें उनके किसी जख्म को हरा कर दिया। प्रश्न यह उठता है आईआईटी कानपुर से बीटेक एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा और रसायन शास्त्र पढ़ाने वाले गुरुजी एमएलसी अरुण पाठक को सही शब्द का चयन करने और सही भाव को ग्रहण करने में सफलता क्यों नहीं मिली।!या फिर यह नहले पे दहला वाला मामला है! या फिर पहले जो कुछ कभी घटित हुआ था जो केवल एडीसीपी और एमएलसी के बीच ही सीमित था, उस हिसाब को बराबर करने की यह प्रक्रिया थी। वेपंस तो जानते हैं पूछना एडीसीपी की अतिरिक्त आक्रामकता को दर्शाता है वहीं राजनीति के चतुर सुजान एमएलसी अरुण पाठक द्वारा बार–बार डील शब्द पर प्रश्न करना उनके रक्षात्मक आक्रमण कौशल को दर्शाता है।

वैसे आपको बता दें कनपुरियों के बीच यह चर्चा आम है महफिल सजाई थी सांसद जी ने और लूट ले गए एमएलसी और एडीसीपी ।

जितने लोग उतने मत

एमएलसी अरुण पाठक और एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा के बीच डील शब्द के चक्कर में हुई नोक झोंक ने उन्हें पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। सोशल मीडिया के जमाने में तिल का ताड़ और बात का बतंगड़ हर रोज बनता ही रहता है। पूरे देश में चर्चा का विषय बनी इस नोंक–झोंक के विषय में सोशल मीडिया यूजर्स की राय तो बंटी हुई है ही, कानपुर में भी स्थानीय स्तर पर जितने मुंह उतनी बातें कहीं जा रही हैं। बहुत से लोग महिला आईपीएस अधिकारी के एटीट्यूड पर सवाल भी उठा रहे हैं। लोगों का कहना है अरुण पाठक जनप्रतिनिधि हैं और पृष्ठभूमि एक टीचर की है, दोनों तरह से वह सम्माननीय हैं। भाजपा संगठन के बहुत से लोग कह रहे हैं योगी जी की सरकार में अफसर अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। भाजपा से जुड़े लोगों का दर्द है कि विपक्षियों की सरकार में जो उनकी दयनीय और उपेक्षित स्थिति प्रशासन में रहती थी, अपनी सरकार होने के बाद भी भाजपाई स्वयं को कमोवेश उसी दशा में पा रहे हैं।

प्रसंगवश

डील करी हमने कभी, हमको नहीं था भान
कब कहां कैसे हुई,पूछ रहे श्रीमान
पूछ रहे श्रीमान,अनुत्तरित दिखतीं अफसर
छिपे व्यंग के तीर, जख्म दे जाते अक्सर
सख्त प्रशासन जानिए,देता नहीं अब ढील
साम दाम औ भेद संग,करता सबसे डील

सीएम आवास योजना में धांधली! गरीब महिला अब भी कच्चे घर में, अपात्रों को बांटे गए आवास

» ग्राम पंचायत मीनापुर की सुमन देवी ने CDO से लगाई न्याय की गुहार

» रोजगार सेवक अंकित बाबू के चाहेतों को मिले पक्के मकान, पात्र महिला आज भी बेघर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री आवास (जीरो प्रॉपर्टी) योजना का वास्तविक लाभ अब भी कई जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ब्लॉक मलासा की ग्राम पंचायत मीनापुर की सुमन देवी पत्नी हरिद्र कुमार का मामला इसका जीवंत उदाहरण है।

सुमन देवी ने मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात को एक प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने लिखा कि उनका कच्चा घर अधगिरा व जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर सकता है। उनके अनुसार, वह एक भूमिहीन व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला हैं, और हर मापदंड पर जीरो प्रॉपर्टी योजना की पात्रता रखती हैं। बावजूद इसके, उन्हें आवास योजना से वंचित कर दिया गया।

चौंकाने वाली बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में आवंटित 15 आवासों में अधिकांश आवास ऐसे परिवारों को दिए गए हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। इनमें से कई के घर पक्के हैं, ट्रैक्टर और खेती-बाड़ी भी मौजूद है। सूत्रों के अनुसार, ये सभी लाभार्थी रोजगार सेवक अंकित बाबू के परिचित हैं, जिन्होंने योजना में अपनी पकड़ और पहुंच के दम पर अपात्रों के नाम जोड़ दिए।

हालांकि, गांव के ग्राम प्रधान को इस धांधली में पूरी तरह निर्दोष माना जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक, प्रधान ने किसी भी तरह की अनुचित संस्तुति नहीं दी। पूरा मामला रोजगार सेवक और उनके पारिवारिक हितों तक सीमित रहा।

सुमन देवी ने अपने पत्र में मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और स्थलीय निरीक्षण कराकर उन्हें आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। उनका कहना है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बिना पक्के घर के वह परिवार समेत हर दिन खतरे में जी रही हैं।

अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करता है या यह शिकायत भी अन्य फाइलों की तरह धूल फांकती रहेगी।

तेज रफ्तार गैस लोडर ने ली मासूम की जान, गांव में मचा कोहराम

गुस्साए ग्रामीणों ने लोडर चालक को पकड़ पुलिस को सौंपा, मां का रो-रोकर बुरा हाल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत भैसायां गांव में मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया, जब घर से चचेरी बहन के साथ शौच के लिए निकली 3 वर्षीय मासूम सोना कठेरिया की तेज रफ्तार लोडर से टक्कर लगने से मौके पर ही मौत हो गई।

पीड़ित पिता सुभाष कठेरिया की बेटी सोना अपनी बहन प्रीत के साथ पास की पुलिया के निकट से गुजर रही थी, तभी पीछे से आ रहे चंदन इंडियन गैस ग्रामीण वितरक के लोडर ने लापरवाही पूर्वक रफ्तार में उन्हें रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सोना को सिर में गहरी चोट आई और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने लोडर और उसके चालक को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मां किरन देवी का रो-रोकर बुरा हाल था, परिजनों का कहना है कि लोडर अक्सर इसी तरह लापरवाही से गांव में दौड़ते हैं लेकिन प्रशासन लापरवाह बना रहता है। पुलिस ने लोडर को जब्त कर लिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि तहरीर मिलते ही चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कायाकल्प योजना ध्वस्त! दो साल बाद भी नहीं बदली स्कूलों की किस्मत

» जर्जर दीवारें, टपकती छतें हादसे को खुला निमंत्रण दे रहे हैं सरकारी स्कूल

» ग्राम प्रधान से लेकर बीईओ तक उदासीन, कायाकल्प बना कागजों की खानापूरी

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों को नया स्वरूप देने के लिए कायाकल्प योजना की शुरुआत की थी। योजना का मकसद था स्कूलों की बुनियादी स्थिति को मजबूत बनाना, मगर कानपुर देहात जिले में यह योजना जमीनी स्तर पर फेल होती नजर आ रही है।

विकास खंड मलासा के गांव टोडरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद चिंताजनक है। स्कूल की पिछली दीवार पूरी तरह से दरारों से भरी है, जबकि सामने की दीवारों की प्लास्टर टूट चुका है। बरसात के समय यह जर्जर भवन कभी भी गिर सकता है, जिससे बच्चों की जान को सीधा खतरा बना हुआ है।

गांववालों का कहना है कि स्कूल की यह हालत वर्षों से ऐसी ही है। कई बार शिकायतें भी हुईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम न छापने की शर्त पर एक ग्रामीण ने बताया,कायाकल्प योजना का पैसा तो आता है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिखता। प्रधान और अधिकारी केवल खानापूरी करते हैं।

स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि शासन से बहुत ही कम बजट आया था। ठेकेदारों ने भी साफ मना कर दिया काम करने से।

दावा किया गया था कि कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों को पेयजल, शौचालय, चारदीवारी, रैंप, रंगाई-पुताई, स्मार्ट क्लास, आदि सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन कई स्कूलों में आज तक टॉयलेट तक नहीं बना। किताबें और फर्नीचर कमरों में धूल फांक रहे हैं।

सरकार जहां करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, वहीं ज़मीनी हकीकत यही है कि बच्चों की जान दांव पर है। क्या फिर से इन स्कूलों का कायाकल्प होगा या सरकार सिर्फ योजना का नाम ही दोहराएगी?

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

8 बीघा जमीन के लिए सास की हत्या कराने वाली शातिर बहू

» प्रेमी अनिल मुठभेड़ में गिरफ्तार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

झांसी। झांसी में जमीन की लालच और अवैध संबंधों की सनसनीखेज कहानी सामने आई है। सास की हत्या में फरार चल रहे मुख्य आरोपी प्रेमी अनिल को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। यह वही अनिल है, जो सास की हत्या की साजिश में पूजा के साथ शामिल था। पूजा पहले ही अपनी बहन के साथ जेल भेजी जा चुकी है। पुलिस ने जब इस हत्याकांड की गहराई से पड़ताल की तो चौंकाने वाली परतें सामने आईं।

रिश्तों को रौंदती पूजा की आपराधिक कहानी

पूजा की शादी झांसी निवासी रवि सिंह से हुई थी। पति की मौत के बाद वह अपने देवर कल्याण सिंह के साथ लिव-इन में रहने लगी। आरोप है कि पति की हत्या भी पूजा ने देवर के साथ मिलकर कराई थी।कुछ समय बाद देवर कल्याण सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद पूजा ने अपने जेठ संतोष सिंह के साथ नाजायज संबंध बना लिए और उसी के साथ रहने लगी।

पुलिस के अनुसार, पति के हिस्से की करीब 8 बीघा जमीन को अपने नाम कराने के लिए पूजा ने सास सुशीला देवी की हत्या की साजिश रची। सास जमीन अपने नाम करने के लिए तैयार नहीं थीं, जिससे नाराज पूजा ने अपने प्रेमी अनिल और बहन के साथ मिलकर सुशीला देवी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी करीब 8 लाख रुपये के जेवरात लेकर फरार हो गए।

छह्वन्न केशव चौधरी की सख्त मॉनिटरिंग में खुला मामला

पूरे मामले का खुलासा झांसी रेंज के डीआईजी श्री केशव कुमार चौधरी के निर्देशन और एसपी के कुशल मार्गदर्शन में हुआ।

पुलिस ने मंगलवार देर रात प्रेमी अनिल की लोकेशन ट्रेस की। घेराबंदी के दौरान मुठभेड़ में अनिल के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

अब तक की कार्रवाई...

बहू पूजा और उसकी बहन पहले ही जेल भेजी जा चुकी हैं।

प्रेमी अनिल को इलाज के लिए पुलिस निगरानी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस अब पूरे प्रकरण में जेठ संतोष सिंह की भूमिका की भी जांच कर रही है।

बेलहरा नगर पंचायत के तालाबों में भरा कूड़ा

» बरसात में बदबू और बीमारियों का खतरा

» सरकार कर रही सौंदर्यीकरण का दावा, जमीनी हकीकत में दिख रहा लापरवाही का गड्ढा

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी। बाराबंकी जिले की बेलहरा नगर पंचायत में जलसंरक्षण की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सिमटती दिख रही हैं। जहां एक ओर प्रदेश सरकार करोड़ों की लागत से नगर पंचायतों में तालाबों का सौंदर्यीकरण और समुद्रीकरण करवा रही है, ताकि बरसात में जलभराव रोका जा सके और भूजल स्तर सुधरे, वहीं बेलहरा में तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है।

नगर पंचायत बेलहरा में कुल 15 वार्ड हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा वार्ड हो जहां तालाबों की स्थिति संतोषजनक हो। अधिकांश तालाबों में सालों से कूड़ा, मलबा और गंदगी फेंकी जा रही है। अब बरसात शुरू होते ही इन तालाबों में पानी तो भरता है, मगर इसके साथ ही भयंकर दुर्गंध और संक्रमण का खतरा भी फैलने लगता है।

स्थानीय वार्ड संख्या 1 के सभासद प्रतिनिधि का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में तालाबों की सफाई का मुद्दा उठाया, लेकिन अधिशासी अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं, वार्ड नंबर 4 की सभासद मृदुल शुक्ला बताती हैं कि उनके क्षेत्र के तालाब भी धीरे-धीरे पाटे जा रहे हैं। इनमें घरेलू कचरा, पुराने कपड़े, प्लास्टिक आदि डाल दिए जाते हैं, जिससे आसपास के इलाके में जलभराव के साथ-साथ संक्रामक रोगों का खतरा भी बना रहता है।

बरसात में महामारी का डर

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब बरसात का पानी तालाब में भरता है तो कूड़े और गंदगी से सड़ांध उठती है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं में इससे उल्टी, बुखार, मच्छरजनित रोग जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से न तो छिड़काव होता है और न ही नगर पंचायत की ओर से साफ-सफाई की कोई विशेष व्यवस्था की जाती है।

तालाब, जो जलस्रोत नहीं, संक्रमण के केंद्र बनते जा रहे

तालाब जहां जल संचयन का जरिया होते हैं, वहीं बेलहरा में यह उपेक्षा और गंदगी के कारण बीमारी फैलाने वाले केंद्र बनते जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि शासन द्वारा आवंटित बजट का सही इस्तेमाल करते हुए, तत्काल प्रभाव से तालाबों की सफाई और सौंदर्यीकरण कराया जाए।यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो बरसात के मौसम में बेलहरा जल संकट और जनस्वास्थ्य के गंभीर खतरे का गवाह बन सकता है।

पोंजी ठग रंजीत मौर्य की अर्जी कोर्ट से खारिज

» अब गैंगस्टर में होगा शिकंजा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। करोड़ों की ठगी, फर्जी कंपनियों का मायाजाल, और जनता को सुनहरे सपने दिखाकर उन्हें लूटने वाला शातिर रंजीत मौर्य अब सलाखों से बाहर नहीं आ सकेगा कम से कम फिलहाल तो नहीं। सीजेएम कोर्ट, अयोध्या ने बहुचर्चित राजनंदिनी गोल्ड और एसएसजी/शिवा ग्रुप घोटाले के मुख्य आरोपी रंजीत मौर्य की जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि जिसने भरोसे की जमीन पर महल बनाकर करोड़ों की चूना लगाने की फितरत पाल रखी हो, उसे अदालत से राहत नहीं मिल सकती।

कानून के शिकंजे में शिकारी

बता दे की मामला अपराध संख्या 577/2024 का है, जिसमें सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी की गतिविधियों की गंभीरता, ठगी गई धनराशि की विशालता, और पीड़ितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। यह वही रंजीत मौर्य है जिसकी जमानत लेते ही वह गायब हो जाता था, और फिर अदालतें जमानतदारों की गर्दन मरोड़ कर पैसा वसूलने लगती थीं। इस बार ऐसा नहीं हुआ जमानतदारों ने खुद अपनी जमानतें वापस ले लीं। डर इस बात का नहीं था कि रंजीत भागेगा, बल्कि इस बात का था कि अदालत अब सीधे-सीधे उन्हें ही ठगी का जम्मिदार मानने लगेगी। राजनंदिनी गोल्ड और शिवा ग्रुप जैसी कंपनियाँ बनाकर रंजीत मौर्य ने अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, बस्ती, बनारस समेत कई जिलों में 'सुनहरे मुनाफे' का झांसा दिया, और लाखों लोगों को करोड़ों की चपत लगा दी। पैसा तो डूबा ही, सम्मान भी गया। इन ठग कंपनियों से कमाए गए धन से रंजीत ने अपने और अपने गैंग के सदस्यों के नाम पर लखनऊ, अयोध्या व अन्य शहरों में बेशकीमती संपत्तियाँ खरीद डालीं। अब इन्हीं संपत्तियों की फेहरिस्त गैंगस्टर एक्ट की विवेचना का हिस्सा बन चुकी है।

गैंग का पूरा नेटवर्क निशाने पर

सूत्रों के मुताबिक रंजीत के गिरोह में

इनायतनगर, बाराबंकी और लखनऊ के कई सक्रिय सदस्य शामिल हैं। इनका डेटा और फोटो पुलिस को मिल चुका है। एक महिला साध्वी जिसकी खुद की आपराधिक पृष्ठभूमि है और सेना नामक संगठन का एक पदाधिकारी इस जाल में गले तक धंसे हैं। सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट, फर्जी कहानियों के जरिए पीड़ितों को डराने और 'सेटलमेंट' की चालें भी पुलिस की रडार पर हैं। व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पोस्ट अब इस गैंग के खिलाफ सबूत बनकर विवेचना में जोड़े जा रहे हैं।

अब कौन बचाएगा?

जिस अयोध्या में रामराज्य की कल्पना होती है, वहाँ रंजीत जैसे ठगों ने लूटराज चलाया। अब ये लुटेरे खुद कटघरे में हैं और शायद लंबे समय तक सलाखों के पीछे रहेंगे। जमानतदार भी अब इनसे तौबा कर चुके हैं। करोड़ों डकारने वाला रंजीत मौर्य, जिसकी ठसक से पहले जमानतदार लाइन में खड़े रहते थे अब अपनी जमानत के लिए 'मददगारों' की भीख मांग रहा है, पर कोई तैयार नहीं।

मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर रिश्वत का सौदा!

» अयोध्या में लेखपाल की करतूत कैमरे में कैद

» वायरल वीडियो से मचा बीकापुर में हड़कंप

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। बीकापुर तहसील क्षेत्र के लेखपाल राजेश श्रीवास्तव का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गया है, जिसने तहसील प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो में राजेश श्रीवास्तव मृतक प्रमाण पत्र बनाने के एवज में पीड़ित से 10 हज़ार रुपए की

मांग करता नजर आ रहा है। यही नहीं, वह कैमरे पर ही यह स्वीकार कर रहा है कि इन पैसों में कुछ हिस्सा ऊपर के अधिकारियों को भी देना होता है।

कटारी गांव के निवासी सालिक राम यादव ने बताया कि उनके पिता रामतेज यादव का निधन 12 मई 2025 को हुआ था। पिता के बैंक खाते से जमा धनराशि निकालने के लिए मृतक प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वह बीकापुर तहसील में पिछले एक महीने से चक्कर काट रहे हैं। शुरुआत में लेखपाल ने प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर दिया, बाद में एसडीएम के हस्तक्षेप पर काम शुरू हुआ, लेकिन फिर भी ?10,000 की रिश्वत की मांग की गई।

सालिक राम ने बताया कि लेखपाल ने फोन कर उन्हें घर बुलाया और कहा, खाली हाथ मत आना, पैसे लेकर आना। जब पीड़ित के पास पूरे पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ?2000 लेखपाल को दिए। यह पूरी घटना उनके साथी ने वीडियो में रिकॉर्ड कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में लेखपाल कहते सुना जा सकता है 20 अधिकारी का दसखत होता है, उसमें पैसे लगते हैं। जांच के बाद दोषी मिलने पर होगी सख्त कार्यवाही-एसडीएम

बीकापुर एसडीएम विकास धर दुबे ने कहा है कि वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तेजतर्रार सीपी जोगेंदर कुमार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से दहले उपद्रवी

अब तक 85 गिरफ्तारी, दबिश जारी; कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं : पुलिस आयुक्त

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

प्रयागराज। शहर की कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों पर अब पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। करछना के भड़ेवरा बाजार में बीते रविवार को हुए उपद्रव के मामले में प्रयागराज के तेजतर्रार और सख्त मिजाज पुलिस आयुक्त जोगेंदर कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मंगलवार तक कुल 85 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

इस बवाल में सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थकों द्वारा की गई तोड़फोड़ और उपद्रव के बाद पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद सीपी जोगेंदर कुमार ने मोर्चा संभाला।

उनके स्पष्ट निर्देश के बाद पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर गहन छानबीन की और सोमवार को 10 और आरोपियों को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया।

प्रयागराज पुलिस की इस सख्ती से साफ हो गया है कि अब कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। आम जनमानस में पुलिस की सख्त और सक्रिय कार्यप्रणाली से विश्वास और भी मजबूत हुआ है।

पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि **कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शांति और सौहार्द के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।**

कार्रवाई के मुख्य बिंदु

- अब तक 85 उपद्रवी गिरफ्तार
- 10 नई गिरफ्तारियां सीसीटीवी वीडियो के आधार पर
- अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश
- सीपी जोगेंदर कुमार खुद मॉनिटरिंग में जुटे

जानकारी के अनुसार, रविवार को सांसद चंद्रशेखर को इसौटा गांव जाने से रोके जाने पर उनके समर्थकों ने बाजार में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की थी। इसके बाद स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लेकिन त्वरित और सख्त पुलिस कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है।

उन्नाव में नियमों से ऊपर पुलिस ?

» सीओ ऑफिस के बाहर 'पुलिस' लिखी गाड़ियां बनीं सवालों के घेरे में

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

उन्नाव। कानून सबके लिए समान है–यह वाक्य अक्सर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जनसभाओं, मीडिया बाइट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में दोहराते हैं। लेकिन जब यही नियम उनके अपने महकमे पर लागू करने की बात आती है, तो नज़ारा कुछ और ही होता है। सीओ उन्नाव कार्यालय के बाहर खड़ी 'पुलिस' लिखी बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों ने इस समानता के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

नियम जनता के लिए, पुलिस के लिए छूट?

हाल ही में सीओ उन्नाव द्वारा पत्रकार की गाड़ी सीज किए जाने की घटना सामने आई थी। वजह थी गाड़ी की नंबर प्लेट का आंशिक रूप से मिटा होना। नियमों की सख्ती का यह उदाहरण सार्वजनिक रूप से सराहनीय भी था। लेकिन अब सवाल उठता है — क्या यही सख्ती विभाग के अपने कर्मचारियों पर भी लागू होती है? सीओ ऑफिस के बाहर दर्ज़नो बाइक दिनभर खड़ी रहती है, जिसकी नंबर प्लेट की जगह बड़े-बड़े अक्षरों में 'पुलिस' लिखा होता है और इस खुले उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यह वाहन आम जनता के सामने कानून की धज्जियाँ उड़ाता नजर आता है।

सीसीटीवी से सामने आ सकता है सच

सीओ कार्यालय के आस-पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनसे यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस प्रकार के वाहन दिनभर वहां खड़े रहते हैं। सवाल यह है कि अगर कानून का पालन सुनिश्चित करना लक्ष्य है, तो फिर शुरुआत खुद विभाग के भीतर से क्यों नहीं?

जनता के बीच गूंज रहे सवाल

क्या पुलिस के वाहन नियमों से ऊपर हैं?क्या पुलिस लिखा होना नियमों से छूट का आधार बन सकता है?

जब सीओ मैडम आम जनता पर नियम लागू करती हैं, तो अपने विभाग पर सख्ती क्यों नहीं दिखती?

प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल

इस तरह की घटनाएं न सिर्फ़ नियमों की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं, बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करती हैं। कानून के नाम पर आम जनता को दंडित करना आसान होता है, लेकिन स्वयं पर वही नियम लागू करना असली प्रशासनिक ईमानदारी की पहचान होती है।

अब निगाहें सीओ उन्नाव पर

इस मामले में सीओ उन्नाव की प्रतिक्रिया अब लोगों की निगाहों में है। क्या वे इस खुले उल्लंघन पर कार्रवाई करेंगी या फिर ये मामला भी अंदर के लोगों के लिए अलिखित छूट का उदाहरण बन जाएगा?

स्टूडेंट का यौन शोषण

16 साल के छात्र पर आया 40 साल की टीचर का दिल

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मुंबई। मुंबई के एक मशहूर स्कूल की 40 वर्षीय महिला टीचर पर अपने स्टूडेंट का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। शिक्षिका पिछले एक साल से 16 वर्षीय छात्र का यौन उत्पीड़न कर रही थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी शिक्षिका पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। इसके बावजूद उसने छात्र को कई मौकों पर परेशान किया।

स्कूल ने साधी चुप्पी : पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफयौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, स्कूल ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। पुलिस के अनुसार, दोस्त ने पीड़ित छात्र से बात की और उसे समझाया कि नवयुवकों और ज्यादा उम्र की महिलाओं का रिलेशनशिप अब आम हो चुका है। तुम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो। ऐसे में दोस्त की बात मानकर छात्र ने शिक्षिका से मिलने के लिए तैयार हो गया।

रूस के भीषण हमलों के बीच अमेरिका ने रोक दी यूक्रेन की सैन्य मदद

बुरे फंसे जेलेंस्की, अब नहीं मिलेगा पेट्रियट एयर डिफेंस और मिसाइलें

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली। यूक्रेन बीते 40 महीने से रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। रूस के हमलों का सामना करने में अमेरिका हथियार ही यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हुए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले खास हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला लिया है। इन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम, तोप के गोले और हवा में मार करने वाली मिसाइले शामिल हैं। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को जाने वाले हथियारों की आपूर्ति रोकने का कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब रूस ने यूक्रेनी शहरों पर हमलों तेज कर दिए हैं। रूस ने हाल ही में कई बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए हैं। ऐसे में रूसी हमलों से बचाव के लिए अमेरिका के ये हथियार बहुत जरूरी हैं।

विशेषज्ञों की रिपोर्ट के मुताबिक, पेंटागन (अमेरिकी रक्षा विभाग) के यूक्रेन को हथियारों की खेप रोकने की वजह अमेरिकी हथियारों का खाली होता

भंडार है। पेंटागन के नीति प्रमुख एलब्रिज कोल्बी के हथियारों के भंडार की समीक्षा के बाद यह चिंता पैदा हुई कि तोपखाने के राउंड, वायु रक्षा मिसाइलों और सटीक हथियारों की कुल संख्या घट रही है। इसके बाद यूक्रेन को भेजे जाने वाले पीएसी-3 पैट्रियट सिस्टम, 155 मिमी आर्टिलरी राउंड, जीएमएलआरएस, स्टिंगर, एआईएम-7 और हेलफायर मिसाइलों की खेप रोक दी गई है।

यूक्रेन की बढ़ेगी चिंता : अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, सटीक तोप के गोले, हेलफायर और दूसरी मिसाइलों की सप्लाई रोकी है।

यूक्रेन इन मिसाइलों को एफ-16 लड़ाकू विमानों के लिए जरिए रूस पर दागता है और एयर डिफेंस के जरिए रूस के हमलों से बचता है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दाग थीं। रूस ने आने वाले समय में फिर से इसी तरह का बड़ा हमला किया तो यूक्रेन संकट में आ जाएगा।

क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ

सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के टॉम कराको का कहना है कि पेंटागन का फैसला यूक्रेन की सेना की कमजोरी को बढ़ा देगा। उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस आपको युद्ध नहीं जिताता है लेकिन इसकी कमी से आप जल्दी हार सकते हैं। अमेरिकी संसद के भी कई सदस्यों ने इस पर चिंता जताई है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर यूक्रे न को हथियार नहीं मिलेंगे तो वह हार जाएगा। मार्सी कैप्टर ने इस पर कहा कि अमेरिका में बने एयर डिफेंस सिस्टम, खासतौर से पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन की रक्षा का केंद्र है। ये सिस्टम हर दिन कई लोगों की जान बचाते हैं। अगर इस सिस्टम की आपूर्ति रोकी जाती है तो यह यूक्रेन के कई सैनिक और नागरिकों की मौत की वजह बन सकता है। ऐसे में अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को फिर से इस पर सोचना चाहिए।

दहेज उत्पीड़न

पति और ससुरालवालों की मांगों से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या

“अपने घर से 300 सोने के सिक्के लेकर आ”

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

चेन्नई। तमिलनाडु में दहेज की मांग को लेकर बहुत हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। तमिलनाडु के तिरुपुर में 300 सोने के सिक्के के लिए प्रताड़ित की गई नवविवाहिता महिला ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सोमवार को बताया कि 27 वर्षीय महिला, जिसकी शादी मात्र ढाई महीने पहले हुई थी, उसने अपने पति और ससुराल वालों को अपने जीवन को समाप्त करने के निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आत्महत्या कर ली।

महिला ने अपने पिता को भेजा ऑडियो संदेश : महिला रिथान्या ने अपने पिता को भेजे एक ऑडियो संदेश में आरोप लगाया कि उसके पति कविनकुमार ने उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने आरोप लगाया कि

उसके ससुर ईश्वरमूर्ति और सास चित्रादेवी ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। महिला ने तंग आकर कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी।

पति ने की मारपीट : पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग की और शादी के लगभग 15 दिन बाद ही समस्याएं शुरू हो गईं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनकी बेटी को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक यातना सहनी पड़ी।

मामले में की जा रही कार्रवाई : महिला से ससुराल वाले कहते थे कि वह अपने घर से 300-500 स्वर्ण सिक्के लेकर आए क्योंकि उसके बाप ने देने को कहा था। दहेज उत्पीड़न के ऐसे आरोपों पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी पर उस अपराध का आरोप तभी लगाया जाएगा जब आरडीओ द्वारा जांच में ऐसी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

गुजरात हाईकोर्ट

चल रही थी सुनवाई, बीयर पीने लगा वकील

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ वकील को जज के सामने बीयर पीते हुए पाया गया। इससे नाराज होकर अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया और वकील के पेश होने पर रोक लगा दी। जजों ने इस हरकत को न्यायालय की अवमानना माना और वकील की उपाधि पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। गुजरात हाईकोर्ट से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। एक केस की वर्चुअल सुनवाई चल ही थी। उसी दौरान वरिष्ठ वकील को जज के सामने बीयर पीते हुए देखा गया, जिससे जज का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने वकील के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया।